दीवानी विविध

माननीय न्यायमूर्ति बल राज तुली के समक्ष

मंदिर मौसूमा, गीता भवन आदि- याचिकाकर्ता।

बनाम

कर अधिकारी (रजिस्ट्रार) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, आदि - प्रतिवादी।

1970 की सिविल रिट संख्या 3962।

29 जुलाई, 1971।

न्यायालय शुल्क अधिनियम (1970 का VII) - अनुसूची II की धारा 7 (v) और अनुच्छेद 17 (iv) - मस्जिद या मंदिर के कब्जे के लिए मुकदमा - उस पर देय न्यायालय शुल्क - चाहे अनुसूची II के अनुच्छेद 17 (vi) के तहत - अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए वाद पत्र में निर्धारित अतिरिक्त संपत्ति का मूल्य - चाहे ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक मस्जिद को बेचा नहीं जा सकता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इसे बेचने का अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति खरीदार को स्वामित्व का शीर्षक दे सकता है। यह आम तौर पर भगवान के घर के रूप में वर्णित किया जाता है और मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रार्थना कहने के लिए उपयोग किया जाता है। मोहम्मडन कानून के अनुसार, एक मस्जिद अतिरिक्त वाणिज्य है और इसका स्वामित्व भगवान में निहित है। केवल यह तथ्य कि एक मस्जिद पर प्रतिकूल रूप से कब्जा किया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिक्री योग्य है, प्रतिकूल कब्जे में आने वाला व्यक्ति अपने बल पर ऐसा करता है, न कि इसलिए कि कोई व्यक्ति उसे शीर्षक देता है। चूंकि एक मस्जिद को बेचा नहीं जा सकता है, इसलिए इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है और इसलिए, मस्जिद के कब्जे के लिए मुकदमे पर, अदालत शुल्क देय अदालत शुल्क अधिनियम, 1870 की अनुसूची II के अनुच्छेद 17 (vi)) के तहत है। अधिनियम की धारा 7 (वी) ऐसे मामले पर लागू नहीं होती है। इसी प्रकार किसी मंदिर के कब्जे के मुकदमे पर, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, देय न्यायालय-शुल्क अधिनियम की अनुसूची II के अनुच्छेद 17 (vi) के तहत है, क्योंकि एक मंदिर अतिरिक्त-वाणिज्य की श्रेणी में आता है और इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है।(पैरा 4)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाद में अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए तय की गई संपत्ति के मूल्य का मतलब संपत्ति का बाजार मूल्य नहीं है यदि संपत्ति अतिरिक्त-वाणिज्य है और इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है।(पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका लिखिए जिसमें प्रार्थना की जाए कि सर्टिओररी की प्रकृति में एक रिट, या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो प्रतिवादी संख्या 16 सितंबर, 1970 द्वारा पारित आदेश

को रद्द करता है। 1 (अनुलग्नक 'ए') और आगे प्रार्थना करते हुए कि रिट याचिका के निर्णय तक याचिकाकर्ता के कब्जे पर रोक लगाई जाए।

आर.एल. अग्रवाल, वकील, याचिकाकर्ताओं की ओर से ।

आर.एस.मित्तल और आई. एस. बलहारा, वकील, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

एम. एस. जैन, एडवोकेट जनरल, हरियाणा।

एम.एस. संधू पंजाब के डिप्टी एडवोकेट जनरल, प्रतिवादी की ओर से

माननीय न्यायमूर्ति बल राज तुली — (1) यह रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित प्रथम अपील पर देय अदालत शुल्क की राशि के संबंध में कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 5 के तहत कर अधिकारी के रूप में इस न्यायालय के रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ निर्देशित है। चूंकि मामला वक्फ संपत्तियों से संबंधित मुकदमों से उत्पन्न अपीलों पर अदालत शुल्क के भुगतान से संबंधित है, इसलिए मैंने पंजाब और हरियाणा के महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया और वकील उनकी ओर से पेश हुए हैं।

1

(2) तथ्य हैं कि पंजाब वक्फ बोर्ड अंबाला छावनी, प्रतिवादी 2 ने अपने अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से याचिकाकर्ता, मंदिर मौसमी गीता भवन के खिलाफ एक मस्जिद के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया, और वाद में संपत्ति का मूल्य 15,000.00 रुपये बताया, लेकिन 15.00 रुपये का एक निश्चित अदालत शुल्क का भुगतान किया पंजाब सरकार द्वारा जारी 3 अक्टूबर की अधिसूचना के अनुसार। वाद में कहा गया था कि प्रतिवादी (इस मामले में याचिकाकर्ता) ने 1953 में मस्जिद पर जबरन कब्जा कर लिया था। मुकदमे को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा डिक्री किया गया था और उस डिक्री के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर की गई है। कार्यालय द्वारा एक आपत्ति उठाई गई थी कि उचित अदालत शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि अधिनियम की अनुसूची II, अनुच्छेद 17 (vi) के तहत देय उचित अदालत शुल्क 19.50 रुपये था, इस आधार पर कि मस्जिद या मंदिर का बाजार मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं था, भले ही इसे अधिनियम की धारा 7 (वी) के तहत एक घर माना जाता है। यह मामला कर अधिकारी के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने विचार व्यक्त किया है कि एक मस्जिद एक संपत्ति है और अपीलकर्ता को इसके मूल्य पर *यथामूल्य* अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा । वाद में वह मूल्य 15,000.00 रुपये बताया गया था, जिसे अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अर्थात वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ता ने कर अधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि भले ही मुकदमे में संपत्ति को घर माना जाए, अदालत शुल्क उसके बाजार मूल्य पर देय है जैसा कि अधिनियम की धारा 7 (वी) में प्रदान किया गया है। मस्जिद को बेचा नहीं जा सकता क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इसे बेचने का अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति किसी खरीदार को स्वामित्व का शीर्षक दे सकता है। मस्जिद को आम तौर पर भगवान के घर या भगवान के निवास के रूप में वर्णित किया गया है और मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रार्थना कहने के लिए उपयोग किया जाता है। एक मस्जिद जो एक वक्फ संपत्ति है, भगवान को समर्पित है और इसलिए, अपरिहार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मस्जिद पर प्रतिकूल रूप से कब्जा किया जा सकता है जैसा कि *मस्जिद, शहीद गंज और अन्य* के रूप में *जानी जाने वाली मस्जिद में आयोजित किया गया है* । *शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर* [1], और *मस्जिद जिसे मस्जिद शहीद गंज के नाम से जाना जाता* है। *शिरो-मणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर और एक अन्य*[2], लेकिन केवल इस तथ्य का मतलब यह नहीं है कि एक मस्जिद पर प्रतिकूल कब्जा किया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिक्री योग्य है। प्रतिकूल कब्जे में आने वाला व्यक्ति अपने बल पर ऐसा करता है, न कि इसलिए कि कोई व्यक्ति उसे शीर्षक देता है। कोई भी संपत्ति जो वक्फ है, चाहे वह मस्जिद हो या कुछ और, मुस्लिम कानून के अनुसार, "*अतिरिक्त* व्यापार "है और इसका स्वामित्व भगवान में निहित है, जैसा कि जस्टिस भिडे ने मस्जिद शाहिद गंज और अन्य बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर में कहा था। चूंकि एक मस्जिद को बेचा नहीं जा सकता है, इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है और इसलिए, देय अदालत शुल्क अधिनियम की अनुसूची II के अनुच्छेद 17 (vi) के तहत है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने अपील के ज्ञापन पर अदालत शुल्क का भुगतान किया है, अधिनियम की धारा 7 (वी) लागू नहीं होती है।

(4)मामले का एक और पहलू है, वह यह है कि संपत्ति को अदालत शुल्क के प्रयोजनों के लिए मुकदमे की तारीख पर देखा जाना चाहिए क्योंकि यह वह संपत्ति है जो मुकदमे की विषय-वस्तु बन जाती है। जिस समय मुकदमा दायर किया गया था, उस समय संपत्ति एक मंदिर थी और एक मंदिर का भी कोई बाजार मूल्य नहीं है। यह *राजगोपडला नायडू बनाम रामसुब्रमण्यम अय्यर और एक अन्य* [3](3) में आयोजित किया गया था। उस फैसले के बाद रंगून उच्च न्यायालय की

[1] ए.आई.आर. 1938 लाह। 369 (एफ.बी.)।

[2] ए.आई.आर. 1940 पी.सी.

[3] ए.आई.आर.1924 मैड 19 (एफ.बी.)।

एक पूर्ण पीठ ने *यू पिन्या और ^ एक अन्य* वी यू *दीपा*[4](4) को नियुक्त किया। *मोतीलाल शिओजी राम* बनाम *नागपुर उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश।शंभूलाल गणपतलाल*[5](5) ने मद्रास और रंगून मामलों (सुप्रा) और *परसोत्तमानंद गिरि* बनाम भारत का हवाला देते हुए कहा कि मंदिर "*रेस्-एक्स्ट्रा-कॉमरेयम*" की श्रेणी में आता *है।मायानंद गिरि*[6], निम्नानुसार देखा गया: –

> "आगे यह तर्क दिया गया है कि विवाद में मंदिर एक सार्वजनिक नहीं बल्कि एक निजी मंदिर है। मुझे समझ नहीं आता कि इससे मंदिर की विपणन क्षमता पर क्या फर्क पड़ता है, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक। मंदिर, जब तक यह एक देवता को समर्पित मंदिर के रूप में खड़ा है, देवता की संपत्ति के रूप में रहता है और परिणामस्वरूप जहां यह इस अर्थ में निजी है कि यह मुख्य रूप से या विशेष रूप से उन व्यक्तियों की पूजा के लिए है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, यह इसे अधिक विपणन योग्य नहीं बनाता है जब बड़े पैमाने पर जनता को वहां प्रवेश करने और पूजा करने की अनुमति होती है। किसी भी मामले में संपत्ति मुख्य रूप से देवता से संबंधित है और इसलिए, इसे *"अतिरिक्त वाणिज्य" की श्रेणी में आना चाहिए।*

ताकि भले ही मुकदमे में संपत्ति को मंदिर माना जाता है, लेकिन इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है और इसलिए, अधिनियम की अनुसूची II के अनुच्छेद 17 (vi) के तहत अदालत शुल्क का सही भुगतान किया गया है।

---

[4] ए.आई.आर.1929 रंगून 134.

[5] ए.आई.आर.1938 नागपुर 481

[6] ए.आई.आर.1932 आल। 593

(5) पंजाब वक्फ बोर्ड के विद्वान वकील याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का उनके तर्क में समर्थन करते हैं कि मस्जिद का कोई बाजार मूल्य नहीं है, लेकिन वह प्रस्तुत करता है कि वाद में संपत्ति का मूल्य वाद में बताया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा उस मुकदमे के प्रतिवादी के रूप में स्वीकार किया गया है; अपील में उसकी ओर से यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि संपत्ति का कोई बाजार मूल्य नहीं है। वाद में जो कहा गया था वह अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए संपत्ति का मूल्य था क्योंकि पंजाब सरकार की अधिसूचना के तहत 15.00 रुपये का एक निश्चित अदालत शुल्क देय था। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि संपत्ति का मूल्य 15,000.00 रुपये है, जिसका मतलब बाजार मूल्य नहीं था। वादी ने कहीं भी इसका बाजार मूल्य नहीं बताया और न ही प्रतिवादी, वर्तमान याचिकाकर्ता ने इसे स्वीकार किया। इसलिए, याचिकाकर्ता 15,000.00 रुपये के मूल्य के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उसने इसे मुकदमे में संपत्ति के बाजार मूल्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए, उस मूल्य पर अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसी तरह की दलीलें दोनों राज्यों के महाधिवक्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने भी दीं। तथापि, मुझे उनकी दलीलों में कोई दम नजर नहीं आता। नतीजा यह होता है कि इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है और कर अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। यह भी माना जाता है कि अपील ज्ञापन के लिए अधिनियम की अनुसूची II के अनुच्छेद 17 (vi) के तहत अदालत शुल्क की आवश्यकता होती है और यदि न्यायालय शुल्क, जैसा कि उसमें निर्धारित किया गया है, का भुगतान किया गया है, तो अपील के ज्ञापन को उचित रूप से मुद्रित माना जाना चाहिए। मामले की परिस्थितियों में, मैं पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।